

क्रान्ति सामय

संस्थापक / संपादक : सुरेश मौर्या

E-mail: krantisamay@gmail.com, www.krantisamay.com

वर्ष: 1 अंक: 46 , 09 नवम्बर, गुरुवार 2017, सूत, हिन्दी दैनिक

मो. 9879141480

4 ओ ब्लॉक आगम नवकार कॉम्पलेक्ष, सचीन रेल्वे स्टेशन के पास, सूत-गुजरात

सार समाचार

लखनऊ में कांग्रेस मनाएगी काला दिवस,निकालेगी कैंडल मार्च

लखनऊ। नोटबंदी के एक वर्ष पूरा होने पर कांग्रेस बुधवार को ‘काला दिवस’ मनाएगी। कांग्रेस कार्यकर्ता काली पट्टी बांधकर प्रदेशव्यापी प्रदर्शन करेंगे। लखनऊ में शाम सात बजे प्रदेश अध्यक्ष राजबब्बर के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला जाएगा। प्रवक्ता अशोक सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नोटबंदी का फायदा दिखाने के लिए 50 दिन का समय मांगा लेकिन ऐसा किया नहीं। नोटबन्दी से देश की अर्थव्यवस्था को हुए व्यापक नुकसान, बढ़ती बेरोजगारी, नोटबन्दी के दौरान आम जनता द्वारा दी गई कुर्बानी, किसानों और आम जनता को हुई परेशानियों को लेकर कांग्रेस आठ नवम्बर को प्रदर्शन करेगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष ने निर्देश दिए हैं कि हर जिला/शहर कांग्रेस कमेटियां दिन में बैठकें, नुक़ड़ सभाएं करके नोटबन्दी से होने वाले नुकसान के बारे में आम जनता को जागरूक करेगी और शाम सात बजे से नोटबन्दी के दौरान हुई दिक्कतों से मरने वाले लोगों की आत्मा की शांति के लिए मोमबत्ती जुलूस निकालेगी। नोटबंदी के एक साल:जानिए देश ने इस फैसले से क्या खोया और क्या पाया उन्होंने कहा कि कांग्रेस नोटबन्दी के दौरान ‘बलिदान’ देने वाले परिवारों की 25-25 लाख रुपये का मुआवजा देने व मृतक के परिवार के एक सदस्य को रोजगार देने की मांग करेगी। यदि मृतक के परिवार की बेटी की शादी है तो उसकी पूरी व्यवस्था कराये जाने से सम्बन्धित प्रधानमंत्री को सम्बोधित ज्ञापन सौंपा जाएगा। लखनऊ में शाम सात बजे कांग्रेस कमेटी मुख्यालय से जीपीओ तक मोमबत्ती जुलूस निकाला जाएगा।

नोटबंदी पर केन्द्र सरकार का जश्न मनाया जनता का उपहास

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने नोटबंदी के एक साल पूरा होने पर केन्द्र सरकार द्वारा जश्न मनाने को देश की जनता का उपहास करार दिया है। उन्होंने कहा नोटबंदी ने देश में आर्थिक संकट खड़ा किया और गरीब जनता के परेशानियां बढ़ायीं।श्री यादव ने मंगलवार को यहां जारी अपने बयान में कहा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बीती 8 नवम्बर 2016 को अचानक नोटबंदी कर दी। इसने देश में निर्माण उद्योग को पूरी तरह ठप कर दिया। इस उद्योग में लगे लाखों मजदूर बेरोजगार हो गये। बड़ी कम्पनियों ने अपने यहां छटनी कर दी। देश की विकास दर में भारी गिरावट आई है। सपा अध्यक्ष ने कहा जिस नोटबंदी के दौर में दर्जनों लोगों की जानें चली गयीं। लोगों के शादी ब्याह और अंतिम संस्कार तक में अडचनें पैदा हो गयीं। मध्यम वर्गीय तथा अल्प वर्ग वाले परिवारों का बजट भी बिगड़ गया। उसको लेकर भाजपा सरकार ‘‘जश्न’’ मनाकर देश की जनता का उपहास उड़ा रही है।श्री यादव ने कहा कि वे शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि रुपया काला-सफेद नहीं होता है, लेन-देन काला सफेद होता है। प्रधानमंत्री ने कालेधन का हौवा खड़ा किया पर स्वयं रिजर्व बैंक की रिपोर्ट कहती है कि जो नोट उसने जारी किए उसमें से 99 प्रतिशत वापस आ गए हैं। आतंकी गतिविधियां रोकने के दावों की दकौकत यह है कि कश्मीर घाटी में पहले से ज्यादा आतंकी घटनाएं घटी हैं। नक्सली गतिविधियां भी थमी नहीं हैं। पृथक्तावादी जगह-जगह सिर उठा रहे हैं।

शहाबुद्दीन हत्याकांड का खुलासा, 3 गिरफ्तार

ब्यूरोबुलंदशहर। आलाकल्ल व हत्या में प्रयुक्त कार बरामद सकिंद्राबाद पुलिस ने शहाबुद्दीन हत्याकांड मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से आलाकल्ल तथा हत्या में प्रयुक्त कार बरामद कर आरोपियों को जेल भेज दिया।पुलिस अधीक्षक नगर प्रवीन रंजन ने बताया कि गत दो नवम्बर को कोतवाली सकिंद्राबाद क्षेत्र के ग्राम तिलबेगमपुल निवासी बाबू खां ने थाना पर अपने भाई शहाबुद्दीन के गत पहली नवम्बर से संधिध परिस्थिति में गायब हो जाने की रिपोर्ट दर्ज करायी थी। पुलिस ने शहाबुद्दीन का शव जिला गौतमबुद्धनगर के थाना जारचा क्षेत्र से बरामद कर उक्त मुकदमा हत्या में तब्दील कर मामले की जांच शुरू की थी। पुलिस की विवेचना में शहाबुद्दीन हत्याकांड में चार युवकों के नाम प्रकाश में आये। इसी कड़ी में पुलिस ने मुखबिरी की सूचना पर गुलाबटो हाईवे पर बने फ्लाईओवर के पास से जिला गौतमबुद्धनगर के थाना जारचा क्षेत्र के ग्राम खटाना निवासी सचिन व कुलदीप तथा थाना दादरी क्षेत्र के ग्राम कैमराला निवासी हरबीर को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से आलाकल्ल के अलावा हत्या में प्रयुक्त मारुति कार बरामद की है।

जेसीबी ने टेम्पो में मारी टक्कर, महिला की मौत

कोहरे में तीन बसें व सेना का ट्रक भिड़ा, 12 घायल

हापड़। ग्रेटर नोएडा

(एसएनबी)। दनकौर कोतवाली क्षेत्र में सोमवार देर शाम एक तेज रफ्तार जेसीबी ने सवारियों से भरे टेम्पो में टक्कर मार दी। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि सात महिलाएं गम्भीर रूप से घायल हो गईं। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया। घायलों में तुलसी विहार दनकौर निवासी कुसुम, सुनीता, रीना, वीरवती, अंजनी व लौंगश्री हैं। ग्रेटर नोएडा स्थित एक निजी कंपनी में नौकरी करती थीं। सोमवार देर शाम सभी एक टेम्पो में सवार होकर दनकौर जा रही थीं। इसी दौरान रास्ते में जेसीबी ने टेम्पो में टक्कर मार दी। सवारियों से भरा टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टेम्पो क्षतिग्रस्त हो गया। टेम्पो में सवार आठ महिलाएं घायल हो गईं। पुलिस ने राहगीरों की मदद से घायलों को दनकौर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। महिला रेखा पत्नी दिनेश की हालत नाजुक देख डॉक्टरों ने कैलाश अस्पताल रेफर कर दिया जहां उसकी मौत हो गई। घायल सात महिलाओं का इलाज दनकौर के



एक अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने हाइवे से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाया तब यातायात सुचारु हो सका मंगलवार तड़के घने कोहरे में सदर कोतवाली क्षेत्र में एनएच-24 बाईपास पर एक रोडवेज, दो प्राइवेट बस व आर्मी का ट्रक आपस में भिड़ गए।

हादसे में एक आर्मी जवान समेत 12 यात्री घायल हो गए। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को बसों से निकालकर एम्बुलेंस के माध्यम से सरकारी अस्पताल में भर्ती

कराया गया। पुलिस ने हाइवे से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाया जिसके बाद यातायात सुचारु हो सका। पिछले तीन दिन से सुबह हल्का कोहरा पड़ रहा था। मंगलवार तड़के घना कोहरा पड़ना शुरू हो गया। जिसके चलते चालकों को वाहन चलाने में परेशानी का सामना करना पड़ा। घने कोहरे से कोतवाली क्षेत्र के एनएच-24 बाईपास पर दो प्राइवेट, रोडवेज व आर्मी का ट्रक आपस में भिड़ गए। हादसे में वाहनों में सवार यात्री व एक आर्मी जवान घायल हो गया। सूचना

पाकर पहुंची पुलिस ने घायलों को बाहर निकाला। पुलिस ने घायल उषा निवासी गांव रसूलपुर, प्रवेश निवासी गांव बनखंडा, शौकत गढ़मुक्तेश्वर, आरुस बनखंडा, कविता गांव रसूलपुर समेत 12 लोग घायल हो गए। पुलिस ने एम्बुलेंस बुलाकर घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। घटना से बाईपास पर भीषण जाम लग गया। पुलिस ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाकर सड़क किनारे खड़ा करवाया जिसके बाद यातायात सुचारु हो सका।

एक्सप्रेस—वे पर पहले टकराईं दो गाड़ियां

आगरा। बुधवार सुबह दिल्ली एनसीआर, नोएडा, पश्चिमी यूपी, ग्रेटर नोएडा में कोहरे की चादर बिछ गई। इस धुंध की वजह से आज कई बड़े हादसे होते होते बचे। आगरा, यमुना एक्सप्रेस वे पर कई वाहन आपस में टकरा गए। इन हादसों में कई लोग घायल भी हुए हैं। मेरठ, ग्रेटर नोएडा में आज सुबह दो हादसे हुए जिसमें एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। यमुना एक्सप्रेस वे पर कोहरे के कारण एक के बाद एक 10

वाहन आपस में टकरा गए। इसमें छह लोग घायल हो गए। घायलों को कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी ही हालत ठीक है। जीरो प्वाइंट से 10 किलोमीटर दूर दनकौर के पास आगरा से नोएडा की तरफ आते समय बुधवार सुबह हादसा हुआ। इस हादसे में एक के बाद 10 गाड़ियां टकरा गईं। इसमें 6 लोग घायल हुए हैं। सभी को कैलाश अस्पताल लाया गया। लोगों को मामूली चोट लगी है। कैलाश अस्पताल में

प्राथमिक उपचार के बाद सभी छुट्टी देने की तैयारी है। हादसे का शिकार लोग दिल्ली के बताए जा रहे हैं। बताया जाता है कि जब दो वाहन टकराए तो इसकी सूचना यमुना एक्सप्रेस वे और पुलिस को दी गई। लेकिन ओके समय पर नहीं पहुंचा। अगर समय पर पहुंच जाते इतने वाहन एक साथ टकराने से बच जाते। मथुरा के अलावा नन्दगांव, बरसाना, कोसी आदि देहात के इलाके भी सुबह कोहरे की गिरफ्त में रहे।

15 साल की उम्र में हुआ था एसिड अटैक, अस्पताल में मिला सच्चा प्यार

नई दिल्ली। प्यार किसी की सूरत से नहीं होता, प्यार सीरत देखकर किया जाता है। यह बात सरोज साहू ने साबित कर दी है। प्रमोदिनी 15 साल की थी जब उनपर एसिड अटैक हुआ था। इस हादसे में प्रमोदिनी अपनी दोनों आंखें गंवा बैठीं और उनका चेहरा गंभीर रूप से झुलस गया था। दरअसल जब वह 15 साल की थी तब एक अर्द्ध सैनिक बल के सैनिक ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया था। जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। इस बात से नाराज होकर उस शख्स ने उनके चेहरे पर एसिड फेंक दिया था। प्रमोदिनी के चेहरे की सर्जरी करने के लिए डॉक्टरों ने उनके पैर के मांस का इस्तेमाल किया। एक बार तो आधे-अधूरे ट्रीटमेंट के बाद उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया, जिसके चलते उनके पैर में इंफेक्शन हो गया। पैर में भरे पस का इलाज कराने के लिए वो एक बार फिर अस्पताल पहुंच गई और इस दौरान उनकी मुलाकात सरोज कुमार साहू से हुई, सरोज अस्पताल की एक नर्स के दोस्त थे। डॉक्टरों ने प्रमोदिनी को मां को बताया कि

प्रमोदिनी के चेहरे की सर्जरी करने के लिए डॉक्टरों ने उनके पैर के मांस का इस्तेमाल किया। एक बार तो आधे-अधूरे ट्रीटमेंट के बाद उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया, जिसके चलते उनके पैर में इंफेक्शन हो गया।

उन्हें चलने में कम से कम चार साल लगेंगे। इस बात को सुनकर मां के सब्र का बांध टूट गया और वो फूट-फूट कर रोने लगी। उन्हें इस तरह रोता देखा सरोज ने उन्हें ढाँढस बंधाया। शुरुआत में प्रमोदिनी और सरोज एक-दूसरे बात तक नहीं करते थे। सरोज रोज-रोज अस्पताल जाते और प्रमोदिनी को दिलासा देते। फिर एक दिन सरोज ने अपनी नौकरी छोड़ दी और दिन के आठ घंटे वो अस्पताल में प्रमोदिनी की सेवा करते रहे और धीरे-धीरे दोनों में प्रेम हो गया। सरोज और प्रमोदिनी पिछले एक साल दिल्ली में साथ-साथ रह रहे हैं और जल्द से जल्द शादी करने की प्लानिंग कर रहे हैं।

कठपुतली कालोनी के ध्वस्तीकरण पर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी

पूरी दिल्ली अनधिकृत : हाईकोर्ट

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने पश्चिमी दिल्ली की कठपुतली कालोनी में चल रहे ध्वस्तीकरण के संबंध में एक अर्जी पर सुनवाई के दौरान मंगलवार को कहा कि पूरी दिल्ली अनधिकृत है।

यह टिप्पणी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की एक पीठ ने उस वक्त की, जब क्षेत्र के कुछ निवासियों का प्रतिनिधित्व कर रहे एक एनजीओ ने

कहा, हाईकोर्ट के 31 अक्टूबर और 1 नवम्बर के आदेशों का उल्लंघन करते हुए नुगियों को ध्वस्त किया गया।

हाईकोर्ट ने अपने दोनों आदेशों में दिल्ली विकास प्राधिकरण को ऐसे व्यक्तियों की झुगियां नहीं गिराने का निर्देश दिया था जो भू-एजेंसी के नियमों के तहत पुनर्वास के योग्य नहीं हैं।एनजीओ ने दावा किया था कि हाईकोर्ट के निर्देशों का डीडीए द्वारा

सख्ती से अनुपालन नहीं किया गया। उसने पीठ के समक्ष यह भी आरोप लगाया कि उसके उस आदेश का भी डीडीए द्वारा अनुपालन नहीं किया गया जिसमें उसने एनजीओ के तीन सदस्यों को पुनर्वास के लिए अयोग्य लोगों की झुगियों की पहचान के लिए क्षेत्र का दौरा करने की इजाजत दी थी।

तीन सदस्यीय समिति को एक महिला कार्यकर्ता ने अदालत में आरोप

लगाया कि मौके पर कुछ पुरुषों ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया।

इस पर पीठ ने क्षेत्र के एसएचओ को तीन सदस्यीय समिति के सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

अदालत ने इसके साथ ही अपने पहले के आदेश को दोहराया कि उसके दिशानिर्देशों का सख्त अनुपालन होना चाहिए। इसके साथ ही पीठ ने मामले को 16 नवम्बर को अगली सुनवाई के लिए

सूचीबद्ध किया।

अदालत ने गत 31 अक्टूबर को स्थल पर ध्वस्तीकरण पर रोक लगा दी थी लेकिन अगले दिन अपने आदेश में संशोधन करते हुए डीडीए को ऐसी झुगियों को ढहाने की इजाजत दी थी जिसके निवासी पुनर्वास के लिए योग्य हैं और स्वेच्छा से कठपुतली कालोनी में और नरेला और आनंद पर्वत शिविरों में चले गए हैं।

35 साल पुराने मामले में चंचल जौनपुर में गिरफ्तार, भेजे गए जेल



जौनपुर। बीएचयू छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष और समाजवादी चिंतक चंचल सिंह 35 वर्ष पुराने मामले में बुधवार को गिरफ्तार कर लिये गए। पुलिस ने उन्हें अपर मुख्य न्यायाधीश पंचम अमर सिंह की कोर्ट में पेश किया। जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। चंचल पर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का आरोप है। 1982 में तत्कालीन अतिरिक्त जिलाधिकारी बदलापुर टीडी गौड़ के साथ कहासुनी के बाद खुद अधिकारी ने धारा 353 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था।

मामला 2 मार्च 1982 का है। अतिरिक्त जिलाधिकारी बदलापुर टीडी गौड़ विकास खण्ड अधिकारी महाराजगंज के कार्यालय का निरीक्षण कर रहे थे। इसी दौरान एक समस्या को लेकर पहुंचे चंचल और टीडी गौड़ में कहासुनी हो गई थी। उनके खिलाफदर्ज रिपोर्ट के मुताबिक चंचल सिंह कार्यालय में घुसे और अपने को छात्रसभा का आल इंडिया प्रेसिडेंट बताते हुए बवाल किया। गौड़ ने चंचल को पुलिस की सुपुर्गरी में देते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना करके 13 अप्रैल 1982 को चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। 5 जून 1984 को चंचल की अनुपस्थिति के कारण बेल बांड निरस्त कर दिया गया था। इसके बाद से लगातार चंचल अनुपस्थित रहे। बुधवार को बदलापुर

पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। चंचल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दुर्धंत सिंह ने वारंट निरस्तीकरण प्रार्थनापत्र दिया। कोर्ट ने प्रार्थनापत्र निरस्त कर चंचल को जेल भेज दिया। चंचल पूर्व रेलमंत्री जार्ज फर्नांडिस के निजी सचिव भी रहे। इस समय कांग्रेस में होने के साथ ही स्वतंत्र पत्रकारिता भी करते हैं।

चंचल ने गिरफ्तारी को राजनीति से प्रेरित बताया

जौनपुर। जेल भेजे जाने से पूर्व चंचल ने बातचीत में अपनी गिरफ्तारी को राजनीति से प्रेरित बताया। कहा कि हाल ही में बीएचयू में हुए बवाल के दौरान उनकी सक्रियता से प्रशासन खोफ खाया हुआ था। चंचल की मांने तो 1982 में वह अपने गृह निवास महाराजगंज ब्लाक के मुख्यालय पर बैठकर चाय पी रहे थे। इतने में उनके एक परिचित भारत यादव पहुंच गये। उन्हें सीमेंट के लिए परमिट चाहिए था। उस दौरान परमिट केवल मजिस्ट्रेट देते थे। जब अतिरिक्त कलेक्टर टीडी गौड़ क्षेत्र का मुआयना करने पहुंचे तो परमिट को लेकर उनसे बातचीत की। इसी दौरान कहासुनी हो गई और मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया। बाद में समझौता हो गया तो मान लिया था कि केस खत्म हो गया है।

मांगों को लेकर हरियाणा कर्मचारियों का प्रदर्शन

फरीदाबाद। हरियाणा कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर सरकार की वादाखिलाफी से खफ। कर्मचारियों ने मंगलवार को प्रदर्शन कर जेल भरो अंदोलन में भाग लिया। आन्दोलन का नेतृत्व कर रहे बिजली विभाग के फरीदाबाद सर्कल सचिव सन्तराम लाम्बा ने बताया कि पिछले दिनों अगस्त में हुई कर्मचारियों की महारैली के दौरान प्रदेश के मुखिया ने सौंपे गए मांगपत्र में से कुछ मांगों पर सहमति जताई थी लेकिन प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों से किए गए वादे के अनुसार मांगों को लागू नहीं किया।

बैंक खाता लिंक कराने के नाम पर 29 हजार तगे युवक के खाते से जालसाज ने निकाले 74 हजार

नोएडा। थाना कविनगर के बम्हैटा गांव निवासी एक युवक के खाते से जालसाज ने 74 हजार रुपए निकाल लिए। पीड़ित को उसके मोबाइल पर आए एसएमएस द्वारा घटना का पता चला। पीड़ित का आरोप है कि इस मामले में उसके द्वारा बैंक प्रबंधन व पुलिस दोनों को प्रार्थना पत्र दिया जा चुका है। लेकिन कहीं भी जांच के लिए सुनवाई नहीं हुई है। वह काफी समय से पुलिस व बैंक के चक्कर काट रहा है। एसएसपी हरिनारायण सिंह को दिए गए प्रार्थना पत्र में दीपक यादव ने बताया कि उसका खाता यूनियन बैंक आफ इंडिया की शाखा में है। कुछ दिन पूर्व उसके मोबाइल पर एक एसएमएस आया कि उसके खाते से तीन बार में एटीएम द्वारा 74 हजार रुपए निकाले गए हैं जबकि एटीएम उसके पास था। मामले की जानकारी के बाद पहले वह बैंक पहुंचा और प्रबंधक से मिला। प्रबंधक द्वारा प्रार्थना पत्र तो स्वीकार कर लिया लेकिन

कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसने एसएसपी को 23 अक्टूबर को प्रार्थना पत्र दिया। एसएसपी ने प्रार्थना पत्र पर मामले की जांच के आदेश दिए। लेकिन तब से लेकर अबतक वह एसएसपी दफ्तर के चक्कर काट रहा है। अभी तक पुलिस द्वारा प्रार्थना पत्र को जांच के लिए थाने व एसओजी टीम को नहीं भेजा गया है। इस संबंध में एसएसपी के पीआरओ सक्सेना ने बताया कि एसएसपी के पास सैकड़ों प्रार्थना पत्र आते हैं। जिन्हें संबंधित विभाग को भेज दिया जाता है। जांच करने के बाद ही कुछ कहा जाएगा। मेडिकल की छात्रा से मोबाइल नंबर और बैंक खाते को आधार कार्ड से लिंक करने के नाम पर 29 हजार रु पए उठा लिए। छात्रा का आरोप है कि आरोपी ने उन्हें फोन कर घर बैठे मोबाइल नंबर और बैंक खाते को आधार कार्ड से लिंक कराने का झांसा दिया था। छात्रा ने मामले की शिकायत कोतवाली सेक्टर-49 पुलिस से की है। मूलरूप से मऊ

निवासी आयाशा हिंडन विहार में अपने रिश्तेदार के यहां रहती हैं। वह ग्रेटर नोएडा के एक कॉलेज से बीफार्मा की पढ़ाई कर रही हैं। उन्होंने बताया कि सोमवार शाम वह घर पर थीं तभी उनके मोबाइल पर एक फोन आया। फोन करने वाले ने कहा कि आपने अभी तक मोबाइल नंबर और बैंक खाते को आधार से लिंक नहीं कराया है। अगर आप घर बैठे मोबाइल नंबर और बैंक खाते को आधार से लिंक कराना चाहती हैं तो आपको पूरी डिटेल बतानी होगी। आयाशा ने बताया कि आरोपी ने झांसे में लेकर उनसे मोबाइल नंबर, बैंक खाते के साथ एटीएम कार्ड की डिटेल ले ली। डिटेल मिलने पर आरोपी ने फोन काट दिया। फोन कटने के बाद उनके मोबाइल पर खाते से पांच बार में 29 हजार रु पए निकलने का मैसेज आया। उन्होंने अपना खाता और एटीएम कार्ड दोनों को ब्लॉक करा दिया है। छात्रा की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच कर रही है।

दान और दुख़ को समान कहा जाता है। थोड़े भी बहूतों को जीत लेते हैं। श्रद्धा से अगर थोड़ा भी दान करो तो परलोक का सुख मिलता है –जातक कथा

गैरकानूनी कार्य

पैराडाइज दस्तावेजों के रूप में जो कुछ हमारे सामने आया है, उसमें यदि सच्चाई है तो यही कहा जा सकता है कि दुनिया भर में ऐसे लोग हैं, जो कर बचाने के लिए उन देशों की कंपनियों में निवेश करते हैं या वहां कंपनियां बना लेते हैं जहां या तो कर नहीं लगता या मामूली कर लगता है। ऐसा करने वालों को अनैतिक तो कहा जा सकता है, लेकिन उन्होंने कानून का उल्लंघन किया ही है, ऐसा कहना जरा मुश्किल है। वैसे पनामा दस्तावेजों की जांच कर रहे बहु एजेंसी समूह (एमएजी) को ही इसकी भी जांच सौंप दी गई है। यह केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अध्यक्ष की अध्यक्षता वाला समूह है, जिसमें सीबीडीटी के दूसरे अधिकारी, प्रवर्तन निदेशालय, रिजर्व बैंक और वित्तीय खुफिया इकाई के प्रतिनिधि शामिल हैं। हालाँकि अभी तक बमूछा की विधि सलाहकार कंपनी के कम्प्यूटर रिकॉर्ड से निकाले गए इन दस्तावेजों से बहुत कुछ साफ नहीं होता है। इसमें दुनिया भर की अनेक क्षेत्रों की हस्तियों के साथ 714 भारतीयों के नाम भी शामिल हैं। किंतु इसमें किसी मामले का पूरा ब्योरा उपलब्ध नहीं है। इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ़ इनवेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स (आईसीआईजे) ने ही पनामा दस्तावेज भी लीक किए थे और उसी ने पैराडाइज दस्तावेज भी सामने लाया है और वही जर्मन अख़बार ज़ीटॉयचे साइटुंग ने इसे छापा है। किंतु आईसीआईजे की वेबसाइट ने भी सभी इकाइयों के नाम और ब्योरे जारी नहीं किए हैं। अगर वाकई इसमें 1 करोड़ 34 लाख दस्तावेज हैं तो फिर इनके अध्ययन में काफी समय बीतेगा। दस्तावेज प्रकाशित करने के साथ ही उसमें यह स्पष्टीकरण देना कि विदेशों में कंपनियों या न्यासों के पंजीकरण वैध कायदे से भी किया जाता है और इसमें किसी नाम आने का मतलब यह नहीं है कि संबंधित व्यक्ति या इकाई ने कानून का उल्लंघन किया ही है, इसकी धार को भीथरा कर देता है। वस्तुतः इस एक पंक्ति के स्पष्टीकरण से पूरा मामला कमजोर हो जाता है। चूंकि इस दस्तावेज में भाजपा एवं कांग्रेस नेताओं के नाम हैं, इसलिए यह राजनीतिक रूप से बड़े बवंडर का कारण नहीं बनेगा। जिन्होंने गैरकानूनी कार्य किया है, उनको सजा मिले और जिन्होंने कानूनी होते हुए भी केवल धन बचाने के लिए अनैतिक किया है, वे देश को जवाब दें कि ऐसा उन्होंने क्या किया। हर देश को यह अधिकार है कि वह अपने देश में कितना कर ले या कर न ले; इसके लिए किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता है।

“माई”

आरक्षण को लेकर एक बार फिर बिहार चंचा में है। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निजी क्षेत्र की कंपनियों में पिछड़ों को आरक्षण देने की वकालत की है। ऐसा कर उन्होंने एक बार फिर ओबीसी को आरक्षण और इसी बहाने सियासी लाभ-हानि का राग भी छेड़ दिया है। ऐसा नहीं है कि नीतीश ने पहली बार ऐसी मांग की है। 2016 में भी उन्होंने निजी क्षेत्रों में पिछड़ों के लिए आरक्षण देने की बात कही थी। हालाँकि उससे पहले पूर्व लोक सभा अध्यक्ष मीरा कुमार, लोक जनशक्ति पार्टी के नेता रामविलास पासवान और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के उपेंद्र कुशवाहा निजी कंपनियों में आरक्षण की मांग कर चुके हैं। लेकिन नीतीश के इस विचार में पिछड़ा वर्ग की सहायभूति के साथ-साथ सुबे में तेजी से बदल रही सियासी आबोहवा की भी अहम भूमिका है। खासकर राज अस्थक्ष लालू प्रसाद यादव के साथ पिछड़ों का सबसे ताकतवर तबका यादव और मुस्लिम वर्ग मजबूती के साथ जुड़ा हुआ है। और इन दोनों समुदाय यादव (14) और मुस्लिम (16) का प्रतिशत 30 है। साथ ही, 2015 में विधान सभा चुनाव में अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग की भी अच्छी-खासी संख्या महागठबंधन के साथ थी। जाहिर है नीतीश के लिएयह चिंता का सबब है। सो, उन्होंने लालू के नजदीक जा चुके अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग जिनमें कोइरी (5 फीसद), कुर्मी (4 फीसद) और अत्यंत पिछड़ा वर्ग (23 फीसद) को अपने पाले में लाने पर गंभीरता से सोचने-विचारने के बाद यह उद्गार व्यक्त किया है। चूंकि बिहार में राजनीति का पासा जातीय गोलबंदी की परख के बाद ही फेंका जाता है। नीतीश इस तथ को भी बेहतर तरीके से जानते-समझते हैं कि यादव और मुस्लिम यानी “माई” वर्ग को लालू से अलग करना नामुमकिन है। यही वजह है कि नीतीश ने आरक्षण का नया दांव खेला है। वैसे भी नीतीश सरकार में उपेक्षित दो दलित नेताओं ने पिछले दिनों नीतीश सरकार के कामकाज पर अंगुली उठाई थी। उनको भीथरा करने के लिए भी नीतीश ने यह मास्टर स्ट्रोक चला है। देखना है, नीतीश के इस “आरक्षण चक्र” का बिहार के साथ राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य पर क्या असर दिखता है? तब तक बहस के बहाने कई सियासी फिजां के बदलने का इंतजार रहेगा।

सत्संग

“अरे आप तो बेहद बुद्धिमान हैं!”

क्यों होता है कि जिस चीज को आप पाना चाहते हैं, एक पल में तो आप उसे बहुत करीब महसूस करते हैं और अगले ही पल वह दूर महसूस होने लगता है? इसकी वजह है आज की दुनिया में हमारे मन को ठीक से संचालित करने पर कोई काम ही नहीं हुआ है। अपनी शिक्षा व्यवस्था से लेकर अपने मन को सिर्फ सूचनाओं से भर रहे हैं। अगर आपके पास दूसरों की तुलना में जरा भी ज्यादा जानकारी हुई तो लोग आपको स्मार्ट समझते हैं। अगर आप बेवजह अपने सिर पर बहुत सारा सामान लेकर चलते हैं तो आमतीर पर लोगों को आपको मूर्ख समझना चाहिए, लेकिन इस मामले में, यानी मन में बेवजह (जानकारी के रूप में) ढेर सारी चीजें ढोने पर लोग आपको स्मार्ट समझते हैं। आज की दुनिया में तो आपको किसी भी चीज की जानकारी के लिए बस अपने फोन में झांकना है और फिर अपने पास से गुजरते किसी आदमी को आकाशगंगा जैसी चीजों के बारे में कुछ बता देना है। सामने वाला खुद ही बोल पड़ेगा, “अरे आप तो बेहद बुद्धिमान हैं!” लेकिन दुर्भाग्य से यहां आप नहीं, बल्कि आपका फोन बुद्धिमान है। आज जानकारी को बुद्धिमानी समझा जाता है जिसे कोई भी मूर्ख हासिल कर सकता है। आप कोई किताब खोल लीजिए और पढ़ लीजिए। लंबे समय तक लोग सोचते रहे कि किताब पढ़ना ही धर्म है। यहां तक कि आज भी कई लोग ऐसा ही सोचते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति साक्षर है तो वह किताब पढ़ सकता है। जब साक्षरता दुर्लभ बात थी, पूरे गांव में सिर्फ एक ही व्यक्ति पढ़-लिख सकता था, जिसे देख कर लोग उस समय हैरत में पड़ जाते थे कि यह इंसान सिर्फ एक किताब में देखकर इतनी सारी बातें बता सकता है, लेकिन जब वे लोग उस किताब में देखते थे तो उनको कुछ समझ नहीं आता था। उन्हें यह चीज बड़ी अद्भुत लगती थी। अब हम मौजूदा दौर की ओर लौटते हैं, आज हमारी शिक्षा व्यवस्था में जिस चीज की कमी खल रही है, वो यह है कि यह हमारे मन की प्रकृति पर ध्यान नहीं दिया जाता और यह नहीं सिखाया जाता कि कैसे हमें इसे संभालना चाहिए, कौन से वे बुनियादी अनुशासन हैं जिसे हमें अपने भीतर लाने की कोशिश करनी चाहिए। यही वजह है कि आप जिस चीज के लिए कोशिश कर रहे होते हैं, एक पल में वह आपको नजदीक व वास्तविक लगने लगती है, लेकिन कुछ देर बाद ही वह फिर एक खोखले वादे सा लगने लगती है।

संपादकीय

“काले धन’ से निजात

वह दुखद घटना उन्हें आज भी भुलाए नहीं भूलती। 31 अक्टूबर, 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या का दिन भी ऐसा ही है, जो भुलाए नहीं भूलता। उस दिन के साक्षी रहे हममें से अधिकांश लोगों को आज भी उस दुखद दिन का पल-पल याद है। आज भी मैं उस दिन की प्रत्येक घटना या बातों को नहीं भूला हूं। बीते वर्ष 8 नवम्बर भी ऐसा ही एक दिन है, जो हममें से अधिकांश लोगों के मन-मस्तिष्क में इसी प्रकार से अंकित हो चुका है। मैं सिकन्दराबाद में अपने मित्रों के साथ घर पर था, और इस खबर को लेकर रोमांचित था कि प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करने वाले थे। मैं और मेरे मित्र टीवी के पास सिमट आए थे, और हमने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की घोषणा सुनी।

सतीश पेडणोकर

रिसर्च सत्रे के मुताबिक, 1955 में या उससे पूर्व जन्मे 95% अमेरिकियों का कहना था कि उन्हें अच्छे से याद है कि केनेडी की हत्या किए जाने के समय वे कहां थे, या क्या कर रहे थे। वह दुखद घटना उन्हें आज भी भुलाए नहीं भूलती। 31 अक्टूबर, 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या का दिन भी ऐसा ही है, जो भुलाए नहीं भूलता। उस दिन के साक्षी रहे हममें से अधिकांश लोगों को आज भी उस दुखद दिन का पल-पल याद है। आज भी मैं उस दिन की प्रत्येक घटना या बातों को नहीं भूला हूं। बीते वर्ष 8 नवम्बर भी ऐसा ही एक दिन है, जो हममें से अधिकांश लोगों के मन-मस्तिष्क में इसी प्रकार से अंकित हो चुका है। मैं सिकन्दराबाद में अपने मित्रों के साथ घर पर था, और इस खबर को लेकर रोमांचित था कि प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करने वाले थे। मैं और मेरे मित्र टीवी के पास सिमट आए थे, और हमने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की घोषणा सुनी : प्यारे भाइयों और बहनों, भ्रष्टाचार और काले धन की कमर तोड़ने के लिए हमने फैसला किया है कि अभी प्रचलित पांच सौ और एक हजार रुपये के करंसी नोटों की आज आधी रात यानि 8 नवम्बर, 2016 के बाद से कोईवैधानिक मान्यता शेष नहीं रहेगी।

’ मेरे पास एक हजार और पांच सौ रुपये के जितने भी नोट थे, उस समय मेरी जेब में थे। कोई ज्यादा नहीं थे, लेकिन इस सच्चाई से ही मेरी कंपकंपी छूट गई कि अब वे मात्र कागज के टुकड़े भर रह जाएंगे। यह भी महसूस हुआ कि बैंक में मेरी हफ्तावार बचत का मोल मात्र चार हजार रुपये रह गया है। एकाएक मैं न केवल लुटा-पिटा बल्कि अपमानित भी महसूस करने लगा। हमारे साथ उस रोज रात के खाने पर मौजूद लोगों में एक ऐसा भी था, जो काफी धनी-मानी था। लेकिन उसके चेहरे पर शिकन तक न थी।

मैं उससे पूछ बैठा कि उसे इस फैसले से क्या कोई झटका नहीं लगा ? उसका उत्तर था कि आप जैसा तो नहीं। फिर उसने जो कहा उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। उसने कहा कि जिनके पास “दो नम्बर’ का पैसा है, वे मूर्खता से पैसे वाले नहीं बन बैठे हैं। जिस पैसे पर कर चोरी की गई होती है, उसे किसी दूसरे रूप में या देश की वित्तीय पणाली की पहुंच से बाहर रखा जाता है। जो मुझे पता चला वह सही ही था क्योंकि शोधों से भी बराबर पता चलता रहा है कि हर साल अधोषि्त आय का करीब आधा हिस्सा संपत्तियों में निवेश कर दिया जाता है, और करीब 44-46क को स्वर्ण और आभूषणों और विदेश में बेनामी संपत्तियों में खपा दिया जाता है। मात्र 4-6% हिस्से को ही नकदी के रूप में रखा जाता है। सरकार ने एकाएक विमुद्रीकरण करके पणाली से लगभग 87ब नकदी यानि 15.44 लाखकरोड़ रुपये सोख लिए। प्रधानमंत्री ने जब घोषणा की कि नोटबंदी से देश को ‘‘काले धन’ से निजात मिल जाएगी तो समूचे राष्ट्र ने इसका स्वागत किया। सरकार ने नोटबंदी का यह कारण भी गिनाया कि जाली नोटों को खत्म करने के साथही

चलते चलते

“मेरी रचना के अर्थ बहुत से हैं,

आज महान गीतकार रमानाथ अवस्ती का जन्मदिन है।-अरे नोटबंदी की बात कर!-तो फिर नोटबंदी-दिवस पर रमानाथ जी के ही गीत थे जाएं। उन्होंने कहा था, “मेरी रचना के अर्थ बहुत से हैं, जो भी तुमसे लग जाए लगा लेना।’ जहां प्रेम-प्रीति, चंदन-घुंघरू की बात हो, वोटर अर्थ लगा लें कि काले धन की या जीएसटी के दुख-दर्द की हो रही है। मोदी जी ने यह गीत साल भर पहले गाया था, “चंदन है तो महकेगा ही, आग में हो या आंचल में। छिप न सकेगा रंग प्रीति का, चाहे लाख छिपाओ तुम। कहने वाले सब कह देंगे, कितना ही भरमाओ तुम। घुंघरू है तो बोलेगा ही, सेज में हो या सांकल में।’ आज गा रहे हैं, “मेरे पंख कट गये हैं, वरना गगन को गाता। मेरे पास वह नहीं है, जो होना चाहिए था, मैं मुस्कराया

तब भी, जब रोना चाहिए था। मुझे सब ने शक से देखा, मैं किसको क्या बताता। वो जो नाव डूबनी है, मैं उसी को खे रहा हूं, तुन्हें डूबने से पहले, एक

मुद्दा

“पब्लिक हेल्थ’

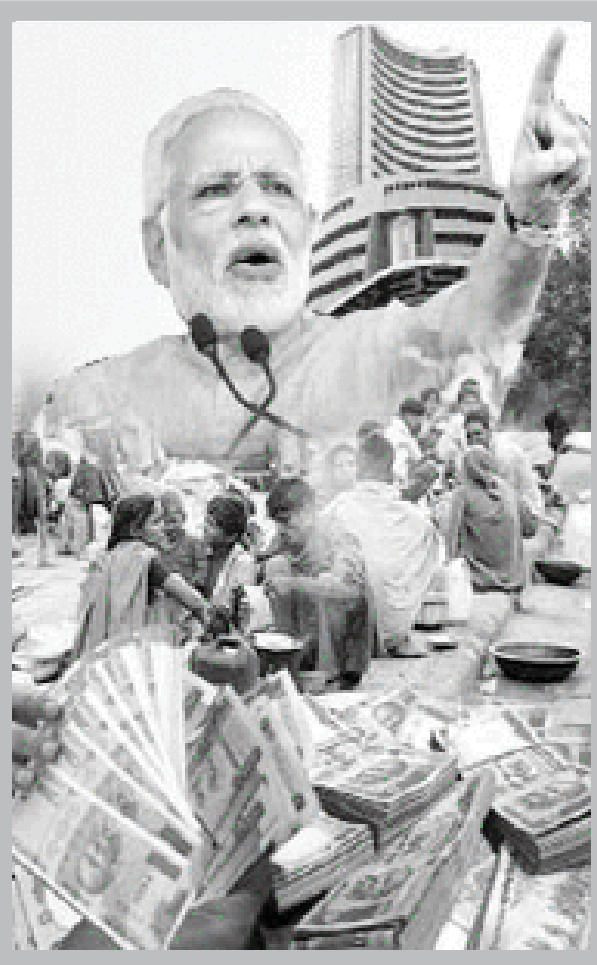
नवम्बर 1 को ऊंचाहार (रायबरेली) स्थित एनटीपीसी के ताप बिजलीघर में हुई भीषण दुर्घटना में अभी तक 33 मजदूर मारे गए हैं व 100 से अधिक घायल हैं। लगभग 60 मजदूरों के गंभीर रूप से घायल होने के समाचार हैं। हालांकि दुर्घटना के कारणों की विस्तृत स्थिति पूरी जांच से ही सामने आएगी, पर आरंभिक जानकारीयों से उच्च स्तर पर गंभीर मानवीय गलतियों के संकेत तो मिलने ही लगे हैं। आरोप है कि बड़ी संख्या में ठेका मजदूरों को खतरनाक स्थितियों में कार्य करने को भेजा गया, बाँयलर के ठीक रख-रखाव या मेनटेनेंस में भी कमी रही। 500 मेगावाट की यूनिट 6 को जल्दबाजी में चालू किया गया, जिससे सुरक्षा पर समुचित ध्यान नहीं दिया जा सका। फिलहाल इस बारे में पूरी जानकारी के लिए चाहे कुछ इंतजार करना पड़े पर विभिन्न क्षेत्रों में समय-समय पर होने वाली कार्यस्थल की दुर्घटनाओं से इतना तो स्पष्ट है कि जरूरी सावधानियां अपना कर इनमें बहुत कमी लाई जा सकती है। हकीकत यह है कि जहां सीवर की सफाई, कुछ तरह के खनन कार्यरे, रसायन व विस्फोट जैसे उद्योगों में दुर्घटनाएं बहुत समय से अधिक होती रही हैं, वहां अब पहले सुरक्षित माने जाने वाले क्षेत्रों जैसे

कृषि में भी जानलेवा दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं जैसा कि हाल में विदर्भ क्षेत्र में पेस्टीसाइड छिड़काव की दुर्घटनाओं में होने वाली बड़ी संख्या में मौतों या किसानों व मजदूरों के जहरीलेपन से प्रभावित होने की घटनाओं से सिद्ध हुआ। आक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के विश्वकोष ने अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के आंकड़ों के आधार पर बताया है कि दुनिया में एक वर्ष में 12 करोड़ आक्यूपेशनल या रोजगार से जुड़ी हुई दुर्घटनाएं होती हैं। इनमें से 210000 दुर्घटनाएं जानलेवा सिद्ध होती हैं। प्रतिदिन, औसतन ऐसे 500 व्यक्ति हैं, जो रोजगार के लिए अपने घर से जाते हैं पर कार्यस्थल पर दुर्घटना के कारण फिर कभी घर नहीं लौटते हैं। विश्व में जो आक्यूपेशनल दुर्घटनाओं को दर है, यहीं भारत में भी मान ली जाए हो तो यहां एक वर्ष में 2 करोड़ आक्यूपेशनल दुर्घटनाएं होती हैं। यह दुर्घटनाएं कृषि, बड़े व छोटे उद्योगों, विभिन्न निर्माण स्थलों, खदानों, वनों आदि विभिन्न कार्यस्थलों पर होती हैं। पर इनमें से बहुत कम दुर्घटनाएं ही संज्ञान में आती हैं जो इनका कोई रिकॉर्ड रखा जाता है। इनसे प्रभावित होने वालों की बहुत कम क्षतिपूर्ति हो पाती है। विशेषज्ञों के मुताबिक यह जरूरी नहीं है कि आधुनिकता व मशीनीकरण के आगमन से सुरक्षा की स्थिति में सुधार हो। कई बार सुरक्षा पर प्रतिकूल असर भी पड़ सकता है। अतः तकनीकी में बदलाव के समय सेफ्टी का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। डॉ. रोनाल्ड स्क्रिब ने अपने अध्ययन में बताया है कि प्रायः सभी दुर्घटनाओं के कई मिले-जुले कारण

होते हैं पर इनमें मानवीय गलतियों की मुख्य भूमिका होती है। गार्डन एम. स्मिथ और मार्क वीजलराइट ने कार्यस्थल दुर्घटनाओं को कम करने में “पब्लिक हेल्थ’ एप्रोच की पैरवी की है। उन्होंने बताया है कि सामान्यतः दुर्घटनाओं को कम करने के प्रयास एक कंपनी या एक इकाई में केंद्रित होते हैं। पर यदि जन-स्वाय के दृष्टिकोण से देखा जाए, जो किसी स्थान के सभी उद्योगों व वहां की आबादी को समग्र रूप से देखते हुए पूरे क्षेत्र का नियोजन सुरक्षा की दृष्टि से करना चाहिए। जहां खतरनाक स्थिति का बुरा असर उद्योग में काम करने वाले लोगों पर पड़ता है, वहां आसपास रहने वाले लोगों को भी इससे जुड़े खतरे सहने पड़ते हैं, जैसे कि भोपाल गैस त्रासदी जैसी दुर्घटनाओं में कई बार देखा गया है। यह देश जानलेवा कार्यस्थल की दुर्घटनाओं में 30 से 40 वर्षों में लगभग 60 से 70 प्रतिशत की कमी कर सके हैं। यह उपलब्धि महत्त्वपूर्ण तो है, पर यदि विश्व स्तर पर देखें तो अभी यह उपलब्धि बहुत कम क्षेत्रों तक सीमित है। इससे अधिक क्षेत्र ऐसे हैं जहां अभी स्थिति बहुत चिंताजनक बनी हुई है। अतः कार्यस्थल की दुर्घटनाओं को कम करने के लिए अभी बहुत प्रयास बाकी हैं। हमारे देश में अभी इस क्षेत्र में ज्यादा प्रगति नहीं हो सकी है व कई चुनौतियां हमारे सामने हैं।

भारत को करना यह चाहिए कि वह समुदी नियंत्रण स्थापित करने तथा अपनी नौसैनिक क्षमताओं को और बढ़ाने की खातिरचीन के साथ सृजनात्मक ढंग से जुड़े। इसके साथ-साथ वह इस लक्ष्य को पाने के लिए हिंद महासागर में अन्य बड़ी शक्तियों के साथ भी जुड़ाव कायम करे। लिहाजा यह नई दिल्ली का जिम्मा है कि वो ये सुनिश्चित करे कि चीन-रूस-पाकिस्तान का त्रिगुट आकार लेकर भारत के सामरिक नुकसान की वजह न बन सके। इस लिहाज से देखें तो मोदी सरकार के समक्ष विवक चुनौती है। चीन को अपने दायरे से दूर रखना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और इसके लिए सामरिक सहभागिताएं करना जरूरी है। चीन की बढ़ती हिमाकतों को देखते हुए हम चैन से नहीं बैठ सकते।

क्रांति समय



राजनेता से ज्यादा विख्यात अर्थशास्त्री हैं, ने अनुमान जताया था कि नोटबंदी के फैसले से जीडीपी में 2ब तक की कमी आ सकती है। उनका आकलन अब तय सन्धि हुआ है। आधिकारिक रूप से जारी किए गए जीडीपी के आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं। 3600 करोड़ रुपये, जो 500 और 2000 रुपये के नये नोट जारी करने में व्यय होने का अनुमान है, को भी शामिल कर लें तो जीडीपी को हुआ नुकसान करीब तीन लाख करोड़ रुपये के करीब बैठता है। यह पैसा कभी वापस नहीं आ सकेगा। सिर्फपागलपन के चलते ऐसा हुआ है। अब यह भी देखें कि भारत की श्रम शक्ति संगठित क्षेत्र की हिस्सेदारी मात्र 7ब ही है। बाकी का श्रम बल असंगठित क्षेत्रमें नियोजित है। वह भी दिहाड़ी कामगारों के रूप में। उनके घरों में नोटबंदी के बाद के दिनों में दो वक्त का चूल्हा तक नहीं जल पाया। इस प्रकार कथित “काले धन’ के नाम पर सरकार ने प्रचलन से वास्तविक मुद्रा प्रवाह को सोख लिया। अर्थव्यवस्था को हो चुके नुकसान से अनजान बने

प्रधानमंत्री ने अब एक नया राग छेड़ दिया है। जोर-शोर से कह रहे हैं कि वह तो उस गरीब-गुरबा के लिए लड़ रहे हैं, जिसे पिछले दशकों के दौरान पैसे वाले उच्च वर्गरे ने लुटा है। इस प्रकार उनने उच्च वर्गरे के खिलाफ्माहौल बना डाला और वर्ग संघर्ष की आंच को सुलगा दिया है। इसे दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य लेकिन कटु सत्य है कि उनके सर्वाधिक मुखर समर्थकों में अधिकांश वे लोग ही हैं जिनके पास “काली दौलत है। कहने की जरूरत नहीं कि नोटबंदी की पूरी कवायद बुरी तरह से नाकाम हुईई।

विस्तारवादी चीन

को रोकने की जुगत

आभा स्वामी

यह अच्छी बात है कि भारत किंचित रुक-रुककर ही सही, लेकिन सामरिक सहभागिताओं के जरिए और खुद अपनी नौसैनिक तैयारियों को मजबूती देते हुए अपनी नौसैन्य सुरक्षा सुदृढ़ करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। पड़ोसी देश चीन की अपनी थल सेना में कटीती कर इसके बजाय वायुसेना व नौसेना में निवेश बढ़ाने की नई प्रस्तावित नीति वास्तव में भारत के लिए चेतावनी की घंटी है। यद्यपि, अब भी भारत का रवैया अग्र-सक्रियतावादी न होकर प्रतिक्रियावादी ही लगता है। पिछले दिनों भारत यात्रा पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन ने सुझाव दिया था कि इस उपमहाद्वीप क्षेत्र में रोड कनेक्टिविटी तथा हिंद-प्रशांत क्षेत्र में पोर्ट कनेक्टिविटी के निर्माण में अमेरिका और भारत को साझेदारी करनी चाहिए, जो चीन की वन रोड, वन बेल्ट (ओबोर) पहल का विकल्प नही। लेकिन भारत ने इस मसले पर उसी तरह चुप्पी साध ली, जिस तरह अमेरिका दक्षिण चीन सागर विवाद में दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों की ओर से दखल देने के मुद्दे पर खामोश बना रहता है।

रेक्स टिलरसन के प्रस्ताव का मुख्य बिंदु यह था कि इस क्षेत्र में चीन की ओबोर परियोजना के जवाब में भारत और अमेरिका को मिलकर एक नियम आधारित और पारदर्शी विकल्प मुहैया कराना चाहिए। इस संदर्भ में उन्होंने बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रोड कनेक्टिविटी पर जोर दिया, कि पाकिस्तान भी इस पहल में शामिल होने के लिए प्रवृत्त हो जाए। हालांकि इस्लामाबाद की बीजिंग के प्रति अति-निर्भरता को देखते हुए यह सोच अवास्तविक लगती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक और बात गौरतलब है। कुछ समय पूर्व जापान के विदेश मंत्री तारो कोनो ने अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ एक उच्चस्तरीय वार्ता का सुझाव दिया था, जिसमें दक्षिण चीन सागर से लेकर हिंद महासागर होते हुए अफ्रीका तक रक्षा सहभागिता और मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने की योजना पर विचार किया जाए। कह सकते हैं कि यह एक बड़ी पहल है और मौजूदा दौर के हिसाब से यह ठीक भी है। लेकिन इस वक्त अहम सवाल यही है कि आगामी 6 नवंबर को जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे तो क्या वो इसे प्रस्ताव को सोद्देश्यपूर्ण तरीके रख सकेंगे और यह भी देखना होगा कि क्या ट्रंप इस पर सार्थक प्रतिक्रिया देते हैं। हिंद महासागर में अपनी सामरिक पहुंच बढ़ाने के लिए चीन श्रीलंका के हंबनटोटा, मालदीव के मराओ के अलावा म्यांमार में भी कुछ ऐसे बंदरगाह विकसित कर रहा है, जहां नौसैनिक शक्ति के पहुंचने की सुविधाएं भी होंगी।

भारत को करना यह चाहिए कि वह समुदी नियंत्रण स्थापित करने तथा अपनी नौसैनिक क्षमताओं को और बढ़ाने की खातिरचीन के साथ सृजनात्मक ढंग से जुड़े। इसके साथ-साथ वह इस लक्ष्य को पाने के लिए हिंद महासागर में अन्य बड़ी शक्तियों के साथ भी जुड़ाव कायम करे। लिहाजा यह नई दिल्ली का जिम्मा है कि वो ये सुनिश्चित करे कि चीन-रूस-पाकिस्तान का त्रिगुट आकार लेकर भारत के सामरिक नुकसान की वजह न बन सके। इस लिहाज से देखें तो मोदी सरकार के समक्ष विवक चुनौती है। चीन को अपने दायरे से दूर रखना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और इसके लिए सामरिक सहभागिताएं करना जरूरी है। चीन की बढ़ती हिमाकतों को देखते हुए हम चैन से नहीं बैठ सकते।

